



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 176]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1975/भाद्र 19, 1897

n. 176] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1975/BHADRA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th September 1975

No 156(9)/74-PY.I.—In Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Resolution No. 156(11)/71-PY.I dated the 1st September, 1972, an Advisory Council was set up which was intended to be a forum to reflect the various points of view on Food and Agricultural problems facing the country, and through which the Government of India could secure the advice and cooperation of producers, consumers, cooperatives, foodgrains trade and economists in the implementation of the Food Policy. In this Resolution, it was specified that the Advisory Council would function for a period of two years. Now that the period of functioning of the Advisory Council constituted on 1st September, 1972 has expired, the Government of India have decided to constitute a new Advisory Council with the following terms of reference :—

- (1) To advise Government in formulation of food policy—procurement, distribution prices, etc.
- (2) To advise Government on measures to be adopted to secure maximum cooperation of trade and processing industry in fulfilling the national objectives of food policy.
- (3) To discuss specific problems of implementation of food policy such as—
 - (a) respective roles of public and private agencies in maintaining price stability;
 - (b) to review measures to remove market imperfections such as inter-State disparities in prices.
 - (c) to suggest methods to improve efficiency of handling grain both to improve quality and reduce operational costs.

- (4) To advise Government in formulation and implementation of policy regarding sugar, vanaspathi and edible oils.
- (5) To advise Government on specific programmes relating to plans for development of storage, marketing and processing industries and nutrition programmes.
2. The Advisory Council shall function for a period of two years.
3. The membership of the Advisory Council shall be as follows :—

Chairman

1. Union Minister of Agriculture and Irrigation.

Vice-Chairman

2. Ministers of State for Agriculture.

Members

3. Minister of State for Finance.
4. Minister of State for Planning.
5. Secretary to the Government of India, Department of Food.
6. Secretary to the Government of India, Department of Agriculture.
7. Secretary, Planning Commission.
8. Chairman, Agricultural Prices Commission.
9. Chairman, Food Corporation of India.
10. Addl. Secretary, Department of Food.
11. Joint Secretary (Admin.), Department of Food.
12. Joint Secretary (Sugar), Department of Food.

Member-Secretary

13. Joint Secretary (D&R), Department of Food.

Non-Official Members

1. Shri Tulsidas Dasappa, Member of Parliament.
2. Shri Raj Deo Singh, Member of Parliament.
3. Shri N. R. Ahirwar, Member of Parliament.
4. Shri M. R. Krishna, Member of Parliament.
5. Shrimati C. Amanna Raja, Ex-MP, 3-6-733, Himayat Nagar, Hyderabad.
6. Shri V. S. Aggarwal, President, Federation of All India Foodgrains Dealers Association, 7A, Elgin Road, Calcutta-20.
7. Shri S. P. Virmani, 15, Golf Links, New Delhi.
8. Shri P. Maruthai Pillai, 330, Thambu Chetty Street, Madras.
9. Prof. M. L. Dantwala, Deptt. of Economics, University of Bombay, Bombay.
10. Shri Devji Rattansey, 25, Chinch Bunder Road, Bombay-9.
11. Shri Santanu Chaudhuri, Director, The United Flour Mills Co. Ltd., 4, Bankshall Street, Calcutta-1.
12. Dr. M. S. Randhawa, Vice Chancellor, Agriculture University, Ludhiana.
13. Dr. B. L. Amla, Director of the Central Food Technological Research Institute, Mysore.
14. Dr. P. V. Sukhatane, Maharashtra Association for the Cultivation of Science, Puna.
15. Shri V. S. Thyagaraja Mudaliar, Chairman, The Tanjore Coop. Marketing Federation, 17/4, Mangambakkam High Road, IInd Floor, Madras-600034.
16. Shri V. V. Dravid, Vice-President, INTUC, Shramshivir, Sanchlatganj, Indore.
17. Chairman, National Agricultural Co-operative Marketing Federation Ltd. (NAFED), Sapna Building, 54, East of Kailash, New Delhi-24.
18. Chairman, Modern Bakeries (India) Ltd., New Delhi.
19. President, National Consumers Federation Ltd., 27, Mahatma Gandhi Marg, Lajpat Nagar, New Delhi-24.
20. Shri S. B. Pandya, Hony. General Secretary, National Tonnage Club, F.2, South Extension Part I, New Delhi-110049.
21. Shri Jagdish Kudeshia, Standing Committee Member, Bharat Krishak Samaj, A.1, Nizamuddin West, New Delhi.

22. Shri Lal Singh Tyagi, President, All India Panchayat Parishad, A-23 Kailash Colony, New Delhi.
 23. Shri Theodoro Badru, Ex-Minister Bihar (Tribal).
 24. Shri Ram Lakhan, Ex-Minister, U.P.
 25. Shri Shantanu Kumar Dass, Ex-Minister, Orissa.
4. The Council is expected to meet at least twice a year.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, all Members of the Advisory Council, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Private Secretary to the President, the Comptroller and Auditor General of India, and the Accountant General, Central Revenues, New Delhi.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

[No. 156(9)/74-PY.I]

G. C. L. JONEJA, Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

सं० 156 (9)/74-पालिसी I.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के दिनांक पहली सितम्बर, 1972 के संकल्प संख्या 156(ii)/71-पालिसी-1 में एक सलाहकार परिषद् स्थापित की गयी थी। इसपरिषद् को देश की खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट करने के लिए एक फोरम बनाने का इरादा था और जिसके माध्यम से भारत सरकार अपनी खाद्य नीति को कार्यान्वित करने में उत्पादकों, उपभोक्ताओं, सहकारी समितियों, खाद्यान्न व्यापारियों और अर्थ शास्त्रियों की सलाह और उनका सहयोग प्राप्त कर सके। इस संकल्प में यह स्पष्ट किया गया था कि यह सलाहकार परिषद् दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी। पहली सितम्बर, 1972 को गठित इस सलाहकार परिषद् का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। भारत सरकार ने एक नई सलाहकार परिषद् गठित करने का निश्चय किया है जिसके निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे:—

- (1) सरकार को खाद्य नीति-अधिप्राप्ति, वितरण मूल्य आदि के बनाने में परामर्श देना।
- (2) सरकार को खाद्य नीति के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापारियों तथा विधायन उद्योग का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना।
- (3) खाद्य नीति की कार्यान्विति सम्बन्धी विविध समस्याओं पर विचार-विमर्श करना जैसे कि —
 - (क) मूल्य में स्थिरता बनाए रखने में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की अपनी अपनी भूमिकाएं ;
 - (ख) बाजार अपूर्णता जैसे कि मूल्यों में अन्तर्राज्यीय अन्तर को समाप्त करने के उपायों की समीक्षा करना ;
 - (ग) अनाज सम्भालने की कायकुशलता सुधारने के तरीके सुझाना जिससे उसकी किस्म सुधारी जा सके और परिवालन व्यय कम किया जा सके।

- (4) चीनी, वनस्पति और खाने के तेलों के बारे में नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सरकार को परामर्श देना ।
- (5) भण्डारण, विपणन, और विधायन उद्योगों तथा पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास की योजनाओं से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देना ।
2. सलाहकार परिषद् दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी ।
3. सलाहकार परिषद् की सदस्यता निम्न प्रकार होगी :—

अध्यक्ष

1. केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री

उपाध्यक्ष

2. कृषि राज्य मंत्री

सदस्य

3. वित्त राज्य मंत्री
4. योजना राज्य मंत्री
5. सचिव, भारत सरकार, खाद्य विभाग
6. सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग
7. सचिव, योजना आयोग
8. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग
9. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम ।
10. अपर सचिव, खाद्य विभाग
11. संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य विभाग,
12. संयुक्त सचिव (चीनी) खाद्य विभाग ।

सचिव सदस्य

13. संयुक्त सचिव (डी० तथा आर०)

गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री तुलसीदास दासप्पा, संसद् सदस्य
2. श्री राज देव सिंह, संसद् सदस्य
3. श्री एन० आर० अहिरवार, संसद् सदस्य
4. श्री एम० आर० कृष्णा, संसद् सदस्य
5. श्रीमती मी० अमप्पा राजा, भूतपूर्व संसद् सदस्य, 3-6-733, हिमायत नगर, हैदराबाद
6. श्री श्री० एस० अग्रवाल, अध्यक्ष, फेडरेशन, अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ, 7-ए, एलगिन रोड, कलकत्ता-20
7. श्री एस० पी० विरमानी, 15, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली
8. श्री पी० मस्थई पिल्ले, 330, थाम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास
9. प्रो० एम० एल० दंतवाला, आर्थिक विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
10. श्री देवजी रत्नसे, 25, चिच बंदर रोड, बम्बई-9

11. श्री शान्तनु चौधरी, निदेशक, यूनाइटेड फ्लोर मिल कं० लि०, 4, बैंगरील स्ट्रीट, कलकत्ता ।
 12. डा० एम० एस० रंधावा, उप कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
 13. डा० बी० एल० ग्रामला, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।
 14. डा० पी० बी० सुखताने, महाराष्ट्र कृषि विज्ञान एसोसिएशन पूना ।
 15. श्री बी० एस० ध्यागराजा मुदालियर, अध्यक्ष, तंजौर सहकारी विपणन संघ, 17/4, नंगमबक्कम हाई रोड, द्वितीय तल, मद्रास-600034 ।
 16. श्री बी० बी० द्रविड़, उपाध्यक्ष, 'इंटैक' श्रमशिविर, संचलतगंज, इंदौर ।
 17. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन लि० (नफेड) सभना बिल्डिंग, 54, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली ।
 18. अध्यक्ष, माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि० नई दिल्ली ।
 19. अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ लि०, 27, महात्मा गांधी मार्ग, लाजपत नगर, नई दिल्ली 24 ।
 20. श्री एस० बी० पांड्या, अवैतनिक महासचिव, राष्ट्रीय टनेज क्लब, एफ-2, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 ।
 21. श्री जगदीश कुदसिया स्थायी समिति सचिव, भारत कृषक समाज, ए-1, पश्चिमी निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।
 22. श्री लाल सिंह त्यागी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पंचायत परिषद्, ए-23, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली ।
 23. श्री थेवडोरो बहू, भूतपूर्व मंत्री, बिहार (जनजातीय) ।
 24. श्री रामलखन, भूतपूर्व मंत्री, 86, भेलपुरा वाराणसी, उ० प्र० ।
 25. श्री शान्तनु कुमार दास, भूतपूर्व मंत्री, उड़ीसा ।
4. आशा है कि परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को प्रति सभी राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों, सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति के निजीसचिव, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक और महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

जी० सी० एल० जुनेजा, सचिव ।

